



EDU TERIA

Prelims Mains
Essay

E - D.N.A.

Daily Newspaper Analysis

By- Nikhil Ranjan

Useful For Prelims

Date: 08 January 2026

नई कहानी आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण कथाकार थे मोहन राकेश



साहित्यकार मोहन राकेश का जन्म 1925 में आज ही अमृतसर में हुआ था। जीविका हेतु अध्यापन से जुड़े। कुछ वर्षों तक सारिका पत्रिका का संपादक भी किया। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे-अधूरे जैसे कालजयी नाटकों में स्वतंत्र भारत के शहरी मध्यमवर्गीय समाज में दरकते रिश्तों, व्यक्ति के एकाकीपन, मनोवैज्ञानिक उलझनों और पारिवारिक विघटन का मार्मिक चित्रण किया। वहीं नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी जैसी कहानियों में मध्यम वर्ग की समस्याओं को गहराई से उकेरा। आखिरी चट्टान तक व परिवेश जैसी उनकी रचनाएं भी काफी चर्चित रहीं।



Dainik Jagaran Page

विल्हेम रॉन्टजेन ने पहली बार एक्स-रे का अवलोकन किया

1895 में आज ही जर्मन भौतिक विज्ञानी विल्हेम रॉन्टजेन ने कैथोड किरणों के साथ प्रयोग करते हुए एक्स-रे का अवलोकन किया था। उन्होंने स्क्रीन पर एक चमक को देखा और महसूस किया कि ये नई एक्स-रे ठोस वस्तुओं से गुजर सकती हैं। इससे भौतिकी और चिकित्सा में क्रांति आ गई।



हरमन होलेरिथ ने अपने पंच्ड कार्ड कैलकुलेटर का पेटेंट कराया

1889 में आज ही अमेरिका के हरमन होलेरिथ ने पंच्ड कार्ड कैलकुलेटर का पेटेंट प्राप्त किया था। 1890 की अमेरिकी जनगणना में तेजी लाने के साथ इस आविष्कार ने डाटा प्रोसेसिंग में क्रांतिकारी बदलाव की नींव रखी। इसने आइबीएम के गठन का मार्ग भी प्रशस्त किया।

Dainik Jagaran Page

मक्का की नई किस्म में अब मिलेगा दूध जैसा पोषण

अल्मोड़ा, वरिष्ठ संवाददाता। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जुड़े विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (वीपीकेएएस), अल्मोड़ा ने मक्का की एक नई और उन्नत किस्म विकसित की है। यह देश की पहली ऐसी मक्का

(भुट्टा) किस्म है, जिसमें तीन पोषक गुण एक साथ मौजूद हैं। मक्का की यह किस्म दूध जैसा पोषण देने में कारगर होगी। इसका नाम 'वी एल त्रिपोषी' रखा गया है और 31 दिसंबर को इसे खेती के लिए अधिसूचित कर दिया गया है।

■ भारतीय वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि, इसका नाम 'वी एल त्रिपोषी' रखा गया है

संस्थान के निदेशक डॉ. लक्ष्मीकांत ने बताया कि यह किस्म दो उन्नत लाइनों के संयोजन से तैयार की गई है। इसमें

उच्च प्रोटीन (क्यूपीएम), विटामिन ए की पूर्ति करने वाला प्रोविटामिन ए और कम फाइटेट जैसे गुण मौजूद हैं। इस मक्का में मौजूद क्यूपीएम प्रोटीन का जैविक मान दूध के प्रोटीन के करीब 90 प्रतिशत तक होता है, जिससे यह बेहद पौष्टिक बन जाती है।

Hindustan Page

भारत पहला बायो-बिटुमेन उत्पादक देश बनेगा : गडकरी

तेयारी

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। देश के सड़क बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अग्रणीकरो युग को शुरूआत होने जा रही है। यहां के वैज्ञानिकों ने पौष्टिक बायो-बिटुमेन उत्पादन करने की तकनीक उपलब्ध करवा दी है। इस प्रकार भारत दुनिया का पहला बायो-बिटुमेन उत्पादक देश बनेगा।

देश के किसान अब केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि सड़कों के लिए बिटुमेनदाता भी बनेंगे। सड़क परिवहन व ग्राममार्ग मंत्री नितिन

गडकरी ने बुधवार को सीएसआईआर-सीआरआरआई द्वारा आयोजित टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कार्यक्रम में उपरोक्त बात कही। उन्होंने कहा कि भारत कृषि अवशेषों से बायो-बिटुमेन का प्याक्साईड उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है। गडकरी ने कहा कि पराली अब सामान्य नहीं बल्कि चनेनी। गडकरी ने कहा कि हर साल पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में पराली जलाना एक गंभीर वायु प्रदूषण का कारण बनता है। अंकाटी के अनुसार केवल इन दो राज्यों में पराली जलाने से 1.6 लाख टन धूल उत्सर्जित होती है।



नई तकनीक के माध्यम से अब इस 600 मिलियन टन से अधिक के कृषि कचरे को सड़कनिर्माण के संरक्षण में बदल जाएगा। गडकरी ने कहा यह

सफल रहा परीक्षण

इस तकनीक का सफल परीक्षण पहले ही वर्ष अक्टूबर 2024 में जैरोहट-लिलान खंड (100 मीटर) और नागपुर-जबलपुर नेशनल हाइवे (1 किमी) पर किया जा चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि बायो-बिटुमेन से बनी सड़कों की मैकेनिकल स्ट्रेंथ (ताकत) बेहतर होगी और इनकी उम्र भी लंबी होगी है।

ये है बायो-बिटुमेन उत्पादक

बिटुमेन पेट्रोलिएम रिफाइनिंग के दौरान प्राप्त होने वाला एक गाढ़ा, चिपचिपा, काला पदार्थ है, जो सड़क निर्माण कार्यों में सामग्री को जोड़ने वाले पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होता है। सीएसआईआर-सीआरआरआई व सीएसआईआर देवराटून द्वारा विकसित तकनीक पेट्रोबैसिस पर आधारित है। इसमें धान के भूसी का उपयोग कर जीरो वेस्ट मॉडल सुनिश्चित होता है।

कुल देश में बिटुमेन की मांग 100 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है। बिटुमेन में केवल 15% बायो-बिटुमेन के मिश्रण से देश को हर साल 4,500 करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

दुनिया में बायो-बिटुमेन पर अभी शोध : दुनिया में जहां अभी भी बायो-बिटुमेन के व्यावसायिक इस्तेमाल पर शोध हो रहा है, वहीं भारत अपनी परंपरागत तकनीक के साथ वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने को तैयार है। यहां न केवल कच्चे तेल पर इमारती निर्माण काम करेगा, बल्कि इलेक्ट्रिक अर्बनइन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर विकासकों को ऊर्जादाता के रूप में नहीं पहचान देगा।

देश में पराली से बनेगा बायो बिटुमिन, 14 कंपनियों को किया गया टेक्नोलाजी ट्रांसफर

जगमग ब्यूरो, नई दिल्ली

मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सोच के साथ कदम बढ़ाते हुए देश के विज्ञानियों ने पराली प्रबंधन का ऐसा तोह निकाला है, जो न सिर्फ प्रदूषण कम करने में मददगार होगा, बल्कि पेट्रो बिटुमिन के अभाव पर प्रतिबंध खंचे होने वाला देश के खजाने का 25-30 हजार करोड़ भी बचाएगा। खास बात है कि यह अनुसंधान प्रयोगशालाओं व फायल्ट प्रोजेक्ट से आगे बढ़ते हुए व्यावसायिक उत्पादन तक पहुंच चुका है।

काउंसिल आफ साइंस एंड इंफ्रस्ट्रक्चर रिसर्च - सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट और सीएसआईआर - इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलिएम देवराटून को इस सफलता को सराहना करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं ग्राममार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रचार) डा.

सीएसआईआर-सीआरआरआई और आरआईआरपी के सफल परीक्षण के बाद व्यावसायिक उत्पादन को हरी झंडी

गडकरी और जितेंद्र सिंह ने कंपनियों को सीपी लाइसेंस, वगेरा पेट्रो-बिटुमिन के अभाव का 25-30 हजार करोड़

जितेंद्र सिंह ने नौ राज्यों की 14 कंपनियों को व्यावसायिक उत्पादन का लाइसेंस प्रदान किया। सीएसआईआर की महानिदेशक एन. कलाहसेल्वी ने बताया कि भारत एक ही वर्ष में जैव-बिटुमिन प्रौद्योगिकी को औद्योगिक और वाणिज्यिक स्तर पर ले जाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में बायो-बिटुमिन के साथ ही कई मूल्यवान सह-उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। यदि सड़कों के लिए जैव-बाइंडर बनने बायो-बिटुमिन को मूल उत्पादन मानें तो उसके अलावा गैसीय

ईंधन, जैव-कोटिंग्स सहित बैटरी, जल रोधन और कई सामग्रियों में उपयोग के लिए उच्च श्रेणी का कार्बन भी मिलता है। उन्होंने खास किया कि पराली से बायो-बिटुमिन बनाने का यह प्रक्रिया प्रदूषण-मुक्त और लागत में काफी किफायती है। महानिदेशक ने बताया कि मेथलव में जोरबंद-लिंगाण एक्सप्रेसवे (एनएच-40) पर बायो-बिटुमिन का उपयोग करके 100 मीटर का एक परीक्षण खंड सफलतापूर्वक बिछाया जा चुका है, जिससे जमीनी स्तर पर इसकी पुष्टि हुई है। इस प्रौद्योगिकी के पेटेंट के लिए आवेदन किया जा चुका है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं ग्राममार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि भारत में अभी प्रतिवर्ष लगभग सौ लाख टन बिटुमिन की आवश्यकता होती है, जिसमें से करीब 50 प्रतिशत का अभाव कानून पड़ता है। इस पर प्रतिवर्ष 25 से 30 हजार करोड़ रुपये खर्च होते हैं।

ब्लॉक होने के बाद भी दुश्मन पर वार करेगा ये मल्टी-फ्रीक्वेंसी ड्रोन

जागरण विशेष

भारत काव्यवक्ता • नई दिल्ली

इंदौर: रक्षा क्षेत्र में ड्रोन की भूमिका लगातार बढ़ रही है। निगरानी से लेकर आवश्यक सामग्री पहुंचाने तक, आधुनिक युद्ध और सुरक्षा व्यवस्था में ड्रोन अहम कड़ी बन चुके हैं। इसी दिशा में इंदौर स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) के छात्रों ने एक ऐसा मल्टी-फ्रीक्वेंसी ड्रोन विकसित किया है, जो दुश्मन द्वारा फ्रीक्वेंसी ब्लाक किए जाने की स्थिति में भी गिरता नहीं और अपना आपरेशन जारी रखता है। एक साथ कई फ्रीक्वेंसी पर काम करने की क्षमता के कारण यह ड्रोन जटिल परिस्थितियों में अधिक भरोसेमंद साबित हो सकता है।

डीएवीवी के इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी संस्थान (आईटी) के विद्यार्थी अमोघ द्विवेदी और पार्थ तिवारी ने इस ड्रोन को विकसित

डीएवीवी की बड़ी उपलब्धि: सेना के टास्क पर डेढ़ साल की रिसर्च के बाद अमोघ द्विवेदी और पार्थ तिवारी ने तैयार किया 10 फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाला ड्रोन

दस फ्रीक्वेंसी पर करता है काम

- ड्रोन एक साथ दस अलग-अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करने में सक्षम है।
- आपरेशन के दौरान यदि एक फ्रीक्वेंसी ब्लाक होती है, तो ड्रोन तुरंत दूसरी फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो जाता है।
- नौ वार तक फ्रीक्वेंसी ब्लाक होने के बावजूद भी यह ड्रोन मिशन जारी रख सकता है।
- आगे के चरण में ड्रोन को इस तरह अपग्रेड करने पर काम हो रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम से बचाव की क्षमता और बेहतर हो सके।

किया है, जिसे 'फ्रीक्वेंसी हाॅपिंग कामिकाजा ड्रोन' नाम दिया गया है। कामिकाजा ड्रोन ऐसे मिशन के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जिनमें लक्ष्य तक पहुंचना ही प्राथमिक उद्देश्य होता है। इन्हें वापसी के लिए नहीं, बल्कि मिशन पूरा करने

रेंज और पेलोड क्षमता

- वर्तमान में ड्रोन की रेंज करीब छह किलोमीटर है।
- दो किलो तक वजन उठाने की क्षमता है।
- इन क्षमताओं के आधार पर ड्रोन को सुरक्षा आपरेशनों में सामग्री पहुंचाने जैसे प्रयोगात्मक उपयोगों के लिए सक्षम बनाया गया है। फिलहाल इसके रेंज और पेलोड क्षमता बढ़ाने पर काम जारी है।

आसान भाषा में समझें

समस्या: सिंगल फ्रीक्वेंसी ड्रोन आसानी से ब्लाक हो जाते हैं। समाधान: मल्टी-फ्रीक्वेंसी हाॅपिंग तकनीक। लाभ: ब्लाक होने के बाद भी आपरेशन जारी। भविष्य: एयर डिफेंस सिस्टम से बेहतर बचाव की क्षमता।

के लिए तैयार किया जाता है। तकनीकी भाषा में इन्हें लाइटरिंग म्यूनिशन भी कहा जाता है। आम तौर पर ड्रोन सिंगल फ्रीक्वेंसी पर संचालित होते हैं। ऐसे में यदि दुश्मन उस फ्रीक्वेंसी को ब्लाक कर दे, तो ड्रोन निष्क्रिय हो सकता है। इसी तकनीकी कमी को दूर करने के लिए छात्रों ने मल्टी-फ्रीक्वेंसी हाॅपिंग सिस्टम विकसित किया है, जिससे ड्रोन ब्लाक होने के बाद सक्रिय रह सकता है। यह दुश्मन क्षेत्र में प्रेनेड लॉच करने या आरडीएक्स ले जाने में सक्षम है।



ड्रोन के साथ अमोघ द्विवेदी और पार्थ तिवारी • नईदुक्ति

हम पिछले दो वर्षों से ड्रोन टेक्नोलॉजी पर अनुसंधान एवं विकास कर रहे हैं। डेढ़ साल की मेहनत के बाद यह मल्टी-फ्रीक्वेंसी ड्रोन तैयार हुआ है, जिसकी टेस्टिंग भी सफल रही है।

-अमोघ द्विवेदी, छात्र, आईटी (डीएवीवी)

ड्रोन को अपग्रेड करने की दिशा में काम जारी है। इसमें रेंज बढ़ाने और एयर डिफेंस सिस्टम से बचाव की क्षमता को और मजबूत करने पर फोकस है।

-पार्थ तिवारी, छात्र, आईटी (डीएवीवी)

आईटी के विद्यार्थियों द्वारा मल्टी-फ्रीक्वेंसी ड्रोन पर किया गया कार्य सफल रहा है। ड्रोन इस तकनीक पर काम कर रहा है और अब इसके अपग्रेडेशन की प्रक्रिया चल रही है। -शानु बाबकर, भवती सीआर, डीएवीवी इन्वेंशन सेक्टर

पेटेंट आवेदन भी किया गया है।



समीक्षा पढ़ने के लिए स्कैन करें।

शपथ: जरिस्टस संगम पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश

पटना विधि संवाददाता। पटना हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने बुधवार सुबह दस बजे पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खॉं ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा व अन्य मंत्रीगण, विधानसभा के अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, हाईकोर्ट के सभी जजों के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य मनन कुमार मिश्रा, महाधिवक्ता



हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ

पीके शाही, बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा, ओडिशा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह, हाईकोर्ट के तीनों अधिवक्ता संघ के पदाधिकारीगण, मुख्य न्यायाधीश के परिजन सहित अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

➤ देखें P 04

पटना जिले में तीन नए साइबर थाने खुलेंगे

पटना, प्रधान संवाददाता। पटना जिले में तीन नए साइबर थाने खोले जाएंगे। वर्तमान समय केवल एक साइबर थाना है। राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद पटना जिले के प्रत्येक एसपी के अधीन एक साइबर थाना होगा।

बुधवार को आईजी (पटना रेंज) जितेंद्र राणा ने साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा समेत जिले के चारों एसपी और डीएसपी के साथ बैठक की। आईजी ने कहा कि साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, इसलिए जिले में चार साइबर थानों की जरूरत हो गई है। वर्तमान में नेहरू पथ पर साइबर थाना है। रोज औसतन छह से सात एफआईआर यहां दर्ज हो रही हैं। साइबर थाने में वर्तमान में 55 सौ शिकायतें दर्ज हैं। इनमें मात्र पांच सौ का अनुसंधान पूरा हुआ है। लगभग पांच हजार मामले अब भी लंबित हैं। तीन और साइबर थाना बनने के बाद अनुसंधानकर्ताओं की संख्या बढ़ जाएगी। पटना मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और ग्रामीण एसपी के अधीन आने वाले केस को संबंधित साइबर थानों में दर्ज किया जा सकेगा। राज्य सरकार से स्वीकृति के बाद पटना मध्य, पश्चिमी, पूर्वी और ग्रामीण क्षेत्र में एक-एक साइबर थाना होगा।

अनुसंधान कार्य में तेजी लाएं: आईजी ने कहा कि साइबर अपराध को लेकर थानों में जो मामले दर्ज कराए गए हैं, उनका निपटारा तेजी से करें। लंबित कांडों का थानावार सूची

■ बढ़ते साइबर अपराध के मद्देनजर आईजी ने सभी एसपी के साथ बैठक की

■ हर एसपी के अधीन अब एक साइबर थाना होगा, अभी एक थाना है जिले में

हर माह एक घटना का अनुसंधान एसपी करेंगे

आईजी ने कहा कि माह में कोई एक बड़ा साइबर से संबंधित दर्ज कांड का अनुसंधान संबंधित पुलिस अधीक्षक स्वयं करें। ऐसे में बड़े कांड का खुलासा भी हो जाएगा। साइबर से संबंधित कांड के अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के लिए टैलीकॉम कंपनियां, सोशल मीडिया, संबंधित बैंक मैनेजर से समन्वय स्थापित कर त्वरित निपटारा करें। पुलिस अधीक्षक साइबर कांडों के अनुसंधान में थानावार एक पुलिस अवर निरीक्षक को नामित करें, जो अनुसंधानकर्ता को सहयोग करें।

बनाकर उन्हें निपटारें। कांडों के अनुसंधान में स्थानीय थानाध्यक्ष, अंचल निरीक्षक, डीएसपी का भी सहयोग लें, ताकि समय पर पूरा किया जा सके। साइबर से संबंधित दर्ज कांडों में घटना घटित होने वाले क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक, अनुसंधान पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष कांड के अनुसंधानकर्ता को सहयोग करें। इससे फायदा होगा कि लोगों को समय पर न्याय मिलेगा।

20 वर्षों में जारी नियमों का संग्रह तैयार

राजस्व विभाग

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राजस्व विभाग ने वर्ष 2003 से 2023 के बीच जारी सभी विभागीय परिपत्रों और नियमों को संग्रहित कर चार खंडों में कम्पोजिट तैयार किया है। बुधवार को उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसका विमोचन किया।

कम्पोजिट प्रकाशित करने का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत लागू राजस्व नियमों, अधिनियमों की प्राथमिक जानकारी राज्य के सभी अधिकारियों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों तक उपलब्ध कराना है। विभागीय कक्ष में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इतने वर्षों



मुख्य सचिवालय में विभागीय पुस्तकों का लोकार्पण करते उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा। साथ में प्रधान सचिव सीके अनिल।

के नियमों और परिपत्रों को एक स्थान पर संकलित करने से विभागीय कार्यप्रणाली में एकरूपता आएगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। कम्पोजिट की उपलब्धता से अधिकारियों को नियमसंगत कार्य करने में सहूलियत होगी। कम्पोजिट

के भाग-1 में भू-अभिलेख, परिमाण तथा चक्रबंदी से संबंधित संग्रह है। भाग-2 में भू-अर्जन तथा भाग-3 में (ए) में खासमहाल, भू-हस्तान्तरण, भूमि बन्दोबस्ती, लोक भूमि अतिक्रमण, राजस्व संग्रहण, भू-लगाव से संबंधित संग्रह है। भाग-4 के अध्याय एक में भूमि दाखिल-खारिज, जमाबंदी, भूमि दखल कब्जा प्रमाणपत्र, अध्याय दो में क्षेत्रीय राजपत्रित स्थापना, अध्याय तीन में क्षेत्रीय अराजपत्रित स्थापना, अध्याय चार में बिहार गजेटियर, अध्याय पांच में कृषि गणना, अध्याय छह में भूमि विवाद निराकरण, भूमि पैमाइश, अध्याय सात में बिहार भूमि न्यायाधिकरण और अध्याय आठ में भू-अर्जन से संबंधित परिपत्र संग्रहित हैं।

रिकॉर्ड: वैभव शतक लगाने वाले सबसे युवा कप्तान बने

बेनोनी, एजेंसी। वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 क्रिकेट में अपना रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन जारी रखा है। सबसे युवा कप्तान बनने के बाद बिहार का 14 साल का यह विस्फोटक बल्लेबाज बुधवार को सबसे युवा शतकवीर कप्तान भी बन गया।

सूर्यवंशी ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे में 74 गेंदों में 10 छक्कों और नौ चौकों से 127 रन की तुकानी पारी खेली। इससे भारतीय अंडर-19 टीम ने सात विकेट पर 393 रन बनाए जो इस टीम के खिलाफ उसका सबसे बड़ा स्कोर है।

पहले विकेट की रिकॉर्ड साझेदारी: सूर्यवंशी ने आरोन जॉर्ज



(118) के साथ पहले विकेट के लिए 154 गेंदों में तबाइ तोड़ 227 रन जोड़े। यह युवा क्रिकेट में भारत को ओर से पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी जबकि कुल तीसरी सबसे बड़ी

03 शतक युवा वनडे में और चार अर्धशतक अब तक 18 मैच में जड़ चुके सूर्यवंशी

09 सौ 73 रन 54.05 की औसत और 164.08 के स्ट्राइक रेट से बना चुके हैं

साझेदारी है। इन दोनों ने अंकुश वेंस और अखिल हरवाडकर का 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। अंकुश और वेंस ने 2013 में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले विकेट के लिए 2108 रन

दक्षिण अफ्रीका को क्लीन स्वीप किया

भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 233 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। मेजबान टीम 394 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए 35 ओवर में 160 रन पर ढेर हो गई। टीम ने 26 गेंदों में मात्र 15 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे।

जोड़े थे। चौथा सबसे तेज शतक: सूर्यवंशी ने अर्धशतक 24 गेंदों तो शतक 63 गेंद में पूरा किया। यह युवा वनडे में पाकिस्तान के कासिम

सूर्यवंशी ने गेंदबाजी में भी हाथ आजमाए, विकेट लेने में सफल

किशन सिंह ने जोरिच वैन शाकविक, अरुनान लागडियन और लयाबो को पवेलियन भेजा। कप्तान मुहम्मद बुलबुलिया को हेंनिल पटेल ने आउट किया। डैनिअल बोसमैन (40), पील जेम्स (41), कॉर्न बोबा (नाबाद 36) और रोल्स (19) ही दोहरे अंक तक पहुंचे। भारत ने सूर्यवंशी सहित सात गेंदबाज आजमाए। सभी ने कम से कम एक विकेट जरूर झटका।

अकरम के साथ चौथा संयुक्त सबसे तेज सैकड़ा है। रिकॉर्ड पाकिस्तान के समीर मिनहास (42 गेंद) के नाम है। दुसरे (52 गेंद) और तीसरे (56 गेंद) पर सूर्यवंशी ही हैं।

बिहार की विकास दर 13 फीसदी के पार, जीएसडीपी में भी उछाल

357 विकास योजनाओं को हरी झंडी, इन पर 16887 करोड़ खर्च होंगे

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार की विकास दर 13.09 फीसदी हो गई है। वर्तमान मूल्य पर वर्ष 2024-25 का जीएसडीपी में वार्षिक वृद्धि दर 13.09 फीसदी है, जबकि स्थिर मूल्य पर वार्षिक वृद्धि दर 8.64 फीसदी है। वहीं बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) बढ़कर 76490 रुपए हो गया है। यह वर्तमान मूल्य पर वर्ष 2024-25 का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। जबकि, स्थिर मूल्य पर यह 40973 रुपए है।

यह जानकारी योजना एवं विकास मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने दी। बताया कि राज्य की 357 विकास योजनाओं को हरी झंडी मिली है। इन पर 16 हजार 887 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में



सूचना भवन में बुधवार को पत्रकारों से बात करते योजना एवं विकास मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव। साथ में विभाग के प्रधान सचिव मयंक बरबड़े, निदेशक रंजीत कुमार।

दिसंबर तक इन योजनाओं को स्वीकृत प्रदान की गयी है। वे बुधवार को सूचना भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने विभाग की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी साझा की। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना के तहत 8.76 लाख युवाओं को सहायता दी गयी है।

इन्हें 1267 करोड़ का भुगतान किया गया है। इसी तरह मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत 72206 योजनाओं को पूरा किया गया है। जबकि, 17621 योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। पूर्ण की गयी योजनाओं पर 3634 करोड़ रुपए खर्च किये गये हैं। इसके अलावा सांसद

स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में 18 वीं लोकसभा सांसदों की अनुशंसा वाली 1108 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। इन पर 117.65 करोड़ खर्च हुए हैं। जबकि, राज्यसभा सांसदों की अनुशंसा पर 261.95 करोड़ की 2914 योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। श्री यादव ने कहा कि षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर दो हजार पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके पूर्व राज्य योजना अंतर्गत 1162 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा पंचायत सुदृढीकरण योजना के तहत 293 भवनों का निर्माण पूर्ण किया गया है। इस अवसर पर विभाग के प्रधान सचिव मयंक बरबड़े, निदेशक रंजीत कुमार मौजूद थे।

तैयारी: बिहार सभी छोटी-बड़ी नदियों की कुंडली बनाएगा

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार अपनी छोटी-बड़ी सभी नदियों को कुंडली तैयार करेगा। उनका एटलस बनाएगा। इसमें नदियों से जुड़ी तमाम जानकारी होगी। किस जिले में कौन सी नदी है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक बहती है, ये सारी जानकारी इस एटलस में रहेगी। सरकार का मानना है कि नदियों का एटलस तैयार हो जाने के बाद भविष्य में नदियों को लेकर कार्ययोजना बनाने में मदद मिलेगी।

जल संसाधन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पिछले दिनों विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने नदियों के एटलस को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की थी। इसमें सभी



संबंधित अभियंताओं को नदियों के एटलस को लेकर निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद विभाग ने सभी क्षेत्रीय अभियंताओं को

दिशा-निर्देश जारी किया है। विभाग ने हाल में पूरे प्रदेश में नदियों का सर्वे किया है। इस समय इस सर्वे की समीक्षा मुख्यालय स्तर पर चल रही है।

■ एटलस में नदियों की पूरी जानकारी होगी
■ सर्वे के बाद जल संसाधन विभाग ने बनायी कार्ययोजना
■ नदी संरक्षण को लेकर योजना बनाने में मिलेगी मदद

अपने जिले की नदी के बारे में जान सकेंगे। जल संसाधन विभाग का मानना है कि इस एटलस के बाद सरकार के साथ-साथ आम लोगों के पास भी नदियों को लेकर सटीक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। आम लोग भी अपने जिलों की सारी नदियों के बारे में भी पूरी जानकारी ले सकेंगे।

एटलस में क्या रहेगा। नदियों के एटलस में नदियों को लेकर उनकी संपूर्ण भौगोलिक जानकारी रहेगी। इसके तहत नदी के नाम, उनके मार्ग और सहायक नदियों की जानकारी भी दी जाएगी। इसके अलावा नदी का उद्गम, मुहाना और जहाँ वह किसी अन्य नदी से मिलती है। नदी बेसिन और जल निष्कासी क्षेत्र की भी जानकारी रहेगी। इसके अलावा जल प्रवाह, नदी नेटवर्क, बांध और जल संसाधन परियोजनाएं उल्लिखित होंगी।

इसके पूरा हो जाने के बाद नदियों की वर्तमान जानकारी विभाग के पास उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन, विभाग नदियों के संबंध में विस्तृत जानकारी

तैयार करना चाहता है। इसी कारण से नदियों को लेकर एक परामर्श बनाया गया है। संबंधित अभियंताओं से इसी विहित प्रपत्र में जानकारी मांगी गई है।

टैरिफ के बावजूद जीडीपी में तेजी रहने का अनुमान

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बुधवार को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 31 मार्च को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के लिए आर्थिक विकास दर का अग्रिम अनुमान जारी किया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सेवा क्षेत्र, निवेश में तेजी और स्थिर खर्च के दम पर अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। पूरे साल के दौरान जीडीपी 201.90 लाख करोड़ रुपये रहने की संभावना है। यह बीते वित्तीय वर्ष के 187.97 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 7.4 प्रतिशत अधिक है। बीते वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश की जीडीपी में वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रही थी। इस हिसाब से बीते वित्तीय वर्ष के मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष में जीडीपी 0.9 प्रतिशत अधिक रहने का अनुमान



रोजगार और नौकरी के मौके
ऊंची जीडीपी दर का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। इससे नई नौकरियाँ उत्पन्न होंगी, खासकर निर्माण, मैन्यूफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी और सेवा क्षेत्र में। वेतन वृद्धि बेहतर हो सकती है।

है। चालू वित्तीय वर्ष में लोकांश, रक्षा एवं अन्य सेवा, वित्तीय, रियल एस्टेट एवं पेशेवर सेवाओं की वृद्धि दर 9.9 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया

जीडीपी के प्रमुख अनुमान

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय	7.4
भारतीय रिजर्व बैंक	7.3
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	6.6
गोल्डमैन सैक्स	6.7
शिव्य बैंक	6.5
एसएडबी	6.5

■ अनुमान प्रतिशत में

अगले वित्त वर्ष में वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान
विदेशी ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर के 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।

गया है। इसके बाद व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने डेटा सुरक्षा उल्लंघन मामले पर आरबीआइ, केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 7 जनवरी (भाषा)।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजता एवं डेटा संरक्षण के अधिकार के उल्लंघन से जुड़ी जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से बुधवार को जवाब तलब किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा डिजिटल ऋण एप के माध्यम से उधारकर्ता के निजता और डेटा संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने पाया कि हिमाक्षी भार्गव द्वारा दायर जनहित याचिका में 'गंभीर चिंताएं' उठाई गई हैं और इस मामले में केंद्र तथा आरबीआइ को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि हम आपके द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर चिंतित हैं। अदालत ने कहा कि हम आरबीआइ से याचिका में लगाए गए आरोपों और 2025 (डिजिटल ऋण) दिशानिर्देशों के प्रवर्तन के लिए की गई कार्रवाई के संबंध में एक

हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हैं। आरबीआइ द्वारा दाखिल किए गए हलफनामों में इन निर्देशों के उल्लंघन के मामले में संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण होना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता कुणाल मदन और मन्वे सरवाणी के माध्यम से जनहित याचिका

दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता युगल जैन और टीना भी उपस्थित रहे। याचिका में आरोप लगाया कि भारतीय रिजर्व बैंक के 2025 के डिजिटल ऋण दिशानिर्देश जारी होने के बावजूद कुछ डिजिटल ऋण देने वाले 'एप' प्रतिबंधित मोबाइल फोन संसाधनों जैसे संपर्क सूचियों और 'काल लागू' तक पहुंच हासिल कर लेते हैं। अत्यधिक व्यक्तिगत और उपकरण-स्तरीय डेटा एकत्र करते हैं और जबकि सहमति मांगने वाले तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। जनहित (ऑनलाइन) में तर्क दिया कि उधारकर्ताओं को सेवाओं का लाभ उठाने की शर्त के रूप में व्यापक और गोपनीय नीतियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है जिससे सहमति अनैच्छिक हो जाती है।

Jansatta Page.

कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कहा फरवरी में बीज विधेयक हो सकता है पेश

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 7 जनवरी।

कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार ने बजट सत्र के पहले चरण में फरवरी में संसद में बीज विधेयक 2025 पेश करने का लक्ष्य रखा है।

उन्होंने एक समाचार एजेंसी से कहा, हमें बीज विधेयक 2025 के लिए सुझावों सहित 9000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन पर विचार

सचिव ने एक समाचार एजेंसी से कहा, हमें बीज विधेयक 2025 के लिए सुझावों सहित 9000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन पर विचार करने के बाद 'कैबिनेट नोट' में इन्हें शामिल किया जाएगा।

करने के बाद 'कैबिनेट नोट' में इन्हें शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य इस विधेयक को बजट सत्र के पहले चरण में पेश करना है। सचिव ने कहा कि मंत्रालय, संसद

के अवकाश के बाद कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 को पेश करने की योजना बना रहा है। बीज विधेयक, 1966 के बीज अधिनियम का स्थान लेगा। इसमें गुणवत्ता और पैकेट पर क्यूआर कोड जैसे आधुनिक मानकों के साथ 'ट्रेसिबिलिटी' सुनिश्चित करने के लिए बीज किस्मों, डीलर और उत्पादकों के लिए अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान है। इसमें निगरानी के लिए केंद्रीय एवं राज्य बीज समितियों की स्थापना का भी प्रावधान है।

जीविका दीदियों की बढ़ सकती है कमाई

नई दिल्ली: ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने और महिलाओं की आमदनी बढ़ाने की दिशा में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और डाक विभाग के बीच बुधवार को एक करार हुआ है, जिससे देश की करीब 12 करोड़ जीविका दीदियों की कमाई हर महीने 15- 30 हजार रुपये तक की बढ़ावा करार करास्ता खुलेगा। (पैज-3)

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के महाभियोग की प्रक्रिया पर संदेह जताया

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 7 जनवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के महाभियोग की प्रक्रिया पर संदेह जताया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने कहा-सवाल यह है कि क्या राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव खारिज करने पर लोकसभा की कार्यवाही भी खत्म हो जाएगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष के जांच कमेटी बनाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने तर्क दिया है कि राज्यसभा और लोकसभा के बीच सलाह मशविरा नहीं हुआ है।

बकील न्यायमूर्ति वर्मा लोकसभा सचिवालय का कहना है कि राज्यसभा ने प्रस्ताव स्वीकार ही नहीं किया है। इसलिए पुरानी व्यवस्था लागू नहीं होती है। अदालत इस मामले की गहराई से जांच कर रही

है। इसमें जजों की जांच से जुड़े कानून की बारीकियों को समझा जा रहा है। यह फैसला भविष्य में महाभियोग की प्रक्रियाओं के लिए बड़ा उदाहरण बनेगा। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत में कड़ी दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि महाभियोग की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं हुआ है। जजसे इंजयरी एक्ट की धारा 3 के तहत एक खास प्रावधान दिया गया है। इससे अनुसूचित अगर् दोनों सदनों में प्रस्ताव आता है, तो संयुक्त परामर्श जरूरी है।

रोहतगी का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष ने राज्यसभा सभापति के फैसले का इंतजार नहीं किया। उन्होंने एकतरफा तरीके से तीन सदस्यों की जांच कमेटी बना दी। वकील ने इसे कानून का उल्लंघन और प्रक्रिया की बड़ी चूक बताया है। अगस्त 2025 में राज्यसभा के उप सभापति ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।

ग्रीनलैंड पर कब्जे की तैयारी में जुटे डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति सैन्य उपयोग समेत विभिन्न विकल्पों पर कर रहे चर्चा

व्हाइट हाउस ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड महत्वपूर्ण

शांतिमंद, रायटर: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की तैयारी में जुट गए हैं। इसके लिए वह सेना के उपयोग और ग्रीनलैंड को खरीदने समेत विभिन्न विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। ट्रंप रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस द्वीप पर नियंत्रण चाहते हैं। हालांकि उनके इस कदम का यूरोपीय देश विरोध कर रहे हैं। डेनमार्क के सांसद रासमुस जालोव ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए एक सहयोगी देश के साथ लगभग युद्ध शुरू कर रहा है।

व्हाइट हाउस ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के अधिग्रहण के विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। वह ग्रीनलैंड को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता के तौर पर देखते हैं। बयान के अनुसार, 'राष्ट्रपति और उनकी टीम इस महत्वपूर्ण विदेश नीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। इस प्रयास में यकीन कमांडर-इन-चीफ के पास अमेरिकी सेना का उपयोग हमेशा एक विकल्प है।'

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रपति और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ग्रीनलैंड को खरीदने पर सक्रिय रूप से चर्चा कर

डेनमार्क के सांसद ने कहा, सहयोगी देश के साथ युद्ध शुरू कर रहे ट्रंप



डोनाल्ड ट्रंप

फाइल

विदेश मंत्री ने कही यह बात

आइएनएस के अनुसार, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने देश के सांसदों से कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप वार्ता के जरिये ग्रीनलैंड हासिल करना चाहते हैं। व्हाइट हाउस का हालिया बयान किसी सैन्य कार्रवाई का संकेत नहीं है। ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं करना चाहते बल्कि उसे खरीदना चाहते हैं। शासन का उद्देश्य ग्रीनलैंड के भविष्य के लिए डेनमार्क पर वार्ता का दबाव डालना है।

रहे हैं। जबकि डेनमार्क के नियंत्रण वाला ग्रीनलैंड लगातार यह कह रहा है कि वह अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। प्रमुख यूरोपीय शक्तियों और कनाडा ने इस आर्कटिक क्षेत्र के लिए एकजुटता दिखाई है। राष्ट्रपति ट्रंप के इस कदम से

इस कारण यह द्वीप चाहते हैं ट्रंप

ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से ग्रीनलैंड की जरूरत है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की उपस्थिति बढ़ रही है। यह रणनीतिक मामला है। ग्रीनलैंड हर जगह रूसी और चीनी जहाजों से घिरा हुआ है। डेनमार्क सुरक्षा करने में सक्षम नहीं होगा। ट्रंप ने पिछले साल भी ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण की बात कही थी। बात दे कि डेनमार्क के नियंत्रण वाला ग्रीनलैंड यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य स्थित है। अमेरिका वहां बैल्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करना चाहता है।

वार्ता चाहते हैं डेनमार्क और ग्रीनलैंड

एपी के अनुसार, डेनमार्क और ग्रीनलैंड अमेरिकी विदेश मंत्री साथ वार्ता चाहते हैं। रूबियो ने बताया कि वह अगले हफ्ते डेनमार्क के अधिकारियों से भेंट करेंगे। इससे पूर्व डेनमार्क की पीएम मेट्टे फ्रेडरिकसन ने कहा था कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा किया तो इसका अर्थ नाटो का अंत होगा। फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन व ब्रिटेन के नेताओं ने कहा, खनिज संपदा से संपन्न यह द्वीप यहां के लोगों का है। रिप्टरजलैंड का कहना है कि ग्रीनलैंड की स्थिति में किसी भी बदलाव के लिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सहमति जरूरी है।

अमेरिका के लंबे समय से सहयोगी डेनमार्क, यूरोप और नाटो में हड़कंप मचा है। इधर, फ्रांस और जर्मनी जैसे सहयोगी देश ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी धमकी से निपटने की योजना पर काम कर रहे हैं।

वेनेजुएला पर दुनिया की आशंका हुई सच

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

वेनेजुएला पर दुनिया की वह आशंका सच हो गई है, जिसमें यह अंदेशा जताया गया है कि अमेरिका ने तेल भंडार के कारण इस देश पर कार्रवाई की। यह आशंका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से सही साबित हुई, जिसमें उन्होंने कहा, वेनेजुएला का अंतरिम प्रशासन अमेरिका को बाजार मूल्य पर तीन से पांच करोड़ बैरल उच्च गुणवत्ता वाला तेल मुहैया कराएगा।

एपी के मुताबिक, ट्रंप ने मंगलवार को अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रथ सोशल पर लिखा कि तेल जहाजों के जरिये सीधे अमेरिका पहुंचाया जाएगा। राष्ट्रपति के रूप में धन पर उनका नियंत्रण होगा, पर इसका उपयोग वेनेजुएला व अमेरिका के लोगों के लाभ के लिए किया जाएगा। इधर, अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस वेनेजुएला को लेकर तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ ओवल ऑफिस में शुक्रवार को बैठक करेगा। इसमें एक्सान, शेवरान और कोनोको फिलिप्स के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। रायटर के अनुसार, अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने बुधवार को कहा, अमेरिका को वेनेजुएला की तेल बिक्री और राजस्व को नियंत्रित करने की जरूरत है ताकि इस देश में बदलाव लाया जा सके। वह अमेरिकी तेल कंपनियों से बात कर रहे हैं। वह वेनेजुएला के तेल को अमेरिकी रिफाइनरियों को बेचना चाहते हैं।

ट्रंप ने कहा, अमेरिका को तीन से पांच करोड़ बैरल तेल मुहैया कराएगा वेनेजुएला

जहाजों से सीधे अमेरिका पहुंचेगा, राष्ट्रपति के रूप में धन पर मेरा नियंत्रण होगा

ऊर्जा मंत्री बोले, अमेरिका को वेनेजुएला की तेल बिक्री को नियंत्रित करने की जरूरत

वेनेजुएला को लेकर तेल कंपनियों के साथ शुक्रवार को व्हाइट हाउस में होगी बैठक

वेनेजुएला पर से कुछ प्रतिबंध हटाए जाएंगे ताकि वहां से दुनियाभर में तेल भेजा जा सके। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, वेनेजुएला में स्थिरता लाने के लिए अमेरिका ने तीन चरणों वाली योजना तैयार की है। इससे पहले काराकास के अप्सरों ने कहा, अमेरिकी कार्रवाई में वेनेजुएला के 24 सैनिकों की मौत हुई। अमेरिका ने शनिवार को वेनेजुएला पर हमला किया। वह राष्ट्रपति निकोलस मद्रुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर न्यूयॉर्क ले आया था।

ट्रंप के कदम पर चीन ने जताई नाराजगी : वेनेजुएला से तेल अमेरिका भेजे जाने की घोषणा के बाद बुधवार को वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। जबकि चीन ने अमेरिका को इस घोषणा पर नाराजगी जताई और इसे धमकाने का कृत्य करार दिया।

भारत-इजरायल आतंकवाद पर साथ

संकल्प

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भारत-इजरायल ने आतंकवाद के सभी रूपों एवं अभिव्यक्तियों के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति बरतने के दृष्टिकोण को दोहराया है। दोनों ने इस खतरे से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बुधवार को फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को गाना शांति योजना की जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं दीं और भारत तथा इजरायल के लोगों के लिए शांति और समृद्धि की कामना की। दोनों नेताओं ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आपसी सहारे विश्वास और दूरदर्शी दृष्टिकोण



के साथ इस वर्ष आगे भारत-इजरायल रणनीतिक साझेदारी व मजबूत करने के साझा प्रार्थमिकताओं की पहचान की। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति शून्य-सहिष्णुता बरतने का दृष्टिकोण दोहराया और इस खतरे से लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि उन्होंने आतंकवाद से और अधिक दृढ़ता के साथ लड़ने के अपने साझा संकल्प की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अपने मित्र प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके मुझे खुशी हुई।

छात्रों से बात करने को उत्सुक: मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि वे परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत बच्चों अभिभावकों से बात को लेकर उत्सुक हैं।



बुधवार को एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा वे परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के सवालों और उनके तजुबों को सुनने को तैयार हैं। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं करीब आ रही हैं। ऐसे में वे बच्चों, अभिभावकों से संवाद को तैयार हैं। मोदी ने एक्स पर कहा कि भारतीय तटस्थक कल के बेड़े में प्रदूषण नियंत्रण पोत 'समुद्रप्रताप' के शामिल होने से आत्मनिर्भर भारत अभियान को कल मिला है।

मंथन



आदित्य कुमार
शिक्षा मामलों के
जानकार

स्कूली शिक्षा में एआइ तकनीक

स्कूली शिक्षा में एआइ को शामिल करने से छात्रों के तकनीकी ज्ञान में वृद्धि होगी। साथ ही भविष्य की वैश्विक ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में हमारा देश अग्रणी भूमिका निभा सकता है

उत्तर प्रदेश में संचालित अटल आवासीय विद्यालय अब आधुनिक तकनीकी शिक्षा और नवाचार के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार प्रकृत अटल आवासीय विद्यालय में इन्वेंशन लेब स्थापित करने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी कला का उद्देश्य प्रयोग और खोज वगैरे से आने वाले छात्रों को ड्रोने टेकनोलॉजी, रोबोटिक्स, आटोमेशन, स्पेस साइंस, 3डी प्रिंटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है।

वस्तुतः एआइ तकनीक धीरे-धीरे सभी स्तरों में फैलती जा रही है। शिक्षा क्षेत्र में भी एआइ ने अपना कमाल दिखाया शुरू कर दिया है। भविष्य में यह तकनीक लोगों के हर काम के लिए जरूरत बन सकती है। स्कूलों में भी बच्चों को एआइ टेकनोलॉजी के बारे में बताया जाने लगा है। बच्चों को एआइ ट्रेनिंग दी जाने लगी है, ताकि बड़े होने के बाद बच्चे एआइ का बेहतरीन तरीके से उपयोग कर सकें।

उल्लेखनीय है कि 21वीं सदी को ज्ञान, तकनीक और नवाचार की सदी कहा जा रहा है। आज का छात्र केवल किताबों तक सीमित नहीं रह सकता, क्योंकि आने वाला समय एआइ, रोबोटिक्स, डाटा और आटोमेशन पर आधारित है। ऐसे में स्कूली शिक्षा में इन सबका समावेश केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि समय की अनिवार्यता बन गया है। यह शिक्षा प्रणाली को टैलेंट विद्या से निष्कलकर कोशल, प्रयोग और नवाचार की ओर ले जाता है। परंपरागत शिक्षा में एक ही कक्षा में सभी छात्रों को एक जैसी गति और

पढ़ाई से पढ़ाया जाता है, जबकि हर छात्र की समझ और रुचि अलग होती है। एआइ आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों की सीखने की गति, गलतियों और कमजोरियों का विश्लेषण कर उन्हें उसी अनुरूप अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराते हैं। इससे कमजोर छात्रों को अतिरिक्त सहायता और तेज छात्रों को उन्नत सीखने के अवसर मिलते हैं। एआइ परीक्षा और मूल्यांकन की प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी बनाता है। यह केवल अंक देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह बताता है कि छात्र कहां ठीक और कहां गलतियां कर रहा है। इससे शिक्षा परिणाम-आधारित न होकर सीखने की प्रक्रिया-आधारित बनती है।



प्रतिकल्पन

अपेक्षाकृत कठिन समझे जाने वाले विषय भी रोचक बन जाते हैं। रोबोटिक्स विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित को व्यावहारिक रूप में जोड़ता है। इससे छात्रों में तार्किक सोच और समस्या-समाधान की क्षमता विकसित होती है। इससे वे वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम होते हैं, जिससे उनमें नेतृत्व, सहयोग और नवाचार की भावना विकसित होती है।

एआइ और रोबोटिक्स शिक्षा से स्कूली स्तर पर कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं। इससे छात्रों में 21वीं सदी के कोशल का विकास होने के साथ ही रोजगार-उन्मुख और उद्यमिता आधारित सोच का विकास हो सकता है। इसके अलावा, इससे छात्रों में रचनात्मकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, जिससे हमारे युवा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकते हैं।

आज तकनीक के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि हमसे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इसे देखते हुए हमें भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा। इसके लिए स्कूल स्तर से ही छात्रों में तकनीक के प्रति रुचि जगानी होगी। ऐसे होने से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी मजबूती दी जा सकती है।

हालांकि इस राह में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे पहली चुनौती प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है। इसके अलावा हमारे स्कूलों में उपकरणों और प्रयोगशालाओं की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। यदि हम इस प्रकार की चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो जाते हैं तो निश्चित रूप से भविष्य में हम एआइ का उपयोग करते हुए चौथी औद्योगिक क्रांति के माध्यम से देश को बहुत लाभ पहुंचा सकते हैं।

लिहाजा भविष्य में यह जरूरी है कि एआइ को केवल एक विषय न मानकर, शिक्षा को एक पद्धति के रूप में अपनाया जाए। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए, कम लागत वाले स्वदेशी तकनीकी समाधान विकसित किए जाएं और क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराई जाए। प्राथमिक स्कूली शिक्षा स्तर से ही छात्रों में तार्किक सोच को पटवृद्धक का हिस्सा बनाया जाए। स्कूली शिक्षा में एआइ और रोबोटिक्स का समावेश भारत को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के साथ ही बौद्धिक रूप से भी सशक्त बनाएगा।



डा. शिवराज प्रसाद
संयोजक, विजन
विकसित भारत नीति
एवं शोध केंद्र

आजकल

सस्ते श्रम नहीं, नवाचार से विकसित बनेगा भारत

वर्तमान विश्व में केवल बड़े पैमाने पर वस्तुओं के निर्माण से समृद्धि हासिल नहीं की जा सकती है। वहीं सिर्फ उत्पादन करने और विश्व के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध कराने से भी कोई राष्ट्र विकसित नहीं बन सकता है। विकसित राष्ट्र के लिए आज सर्वाधिक आवश्यकता ज्ञान, नवाचार और बौद्धिक संपदा पर अधिकार की है। आज जब विश्व चौथी औद्योगिक क्रांति के दौर में प्रवेश कर रहा है तो राष्ट्रों का निर्माण केवल हाथों की मेहनत से नहीं, बल्कि दिमागों की शक्ति से होता है। निर्माण से आगे बढ़कर उच्च गुणवत्ता के सृजन को प्राथमिकता देने पर ही भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है

आज के वैश्विक युग में यह धारणा आम है कि यदि कोई देश बड़े पैमाने पर वस्तुओं का निर्माण करता है तो वह स्वतः समृद्ध हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल और कठोर है। केवल उत्पादन करना और दुनिया के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करना किसी राष्ट्र को विकसित नहीं बनाता, विकसित राष्ट्र वही बनते हैं जो ज्ञान, नवाचार और बौद्धिक संपदा पर अधिकार रखते हैं। इस सच्चाई को समझने के लिए आइए हमें एक उदाहरण प्रस्तुत करें। चीन में एक आइफोन को असेंबल करने की लागत लगभग 10-15 डॉलर यानी लगभग एक हजार रुपये होती है, जबकि वही फोन वैश्विक बाजार में 70 हजार से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक विकत है।

इसका कारण यह है कि उस देश की श्रम शक्ति ही है जो वस्तुओं को सस्ते में बनाती है। आइफोन सिस्टम और सॉफ्टवेयर अमेरिका तथा भारत जैसे देशों के इंजीनियर विकसित करते हैं, और ब्रांड वैल्यू परिचयों कंपनियों के पास रहती हैं। अर्थात् वास्तविक लाभ उस देश को मिलता है जो सौचता है। नवाचार करता है और बौद्धिक अधिकारों का स्वामी होता है, न कि उस देश को जो केवल उत्पाद को जोड़ने का कार्य करता है।

सस्ते श्रम का धारः भारत जैसे विकासशील देशों में दरवाहों तक यह मान्यता बनी रही कि हमारी सस्ती बड़ी ताकत सस्ता श्रम है और इसी के आधार पर हमने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका तय की। प्रारंभिक दौर में इस रणनीति ने रोजगार के अवसर तो दिए, लेकिन लंबे समय में यही सोच हमारे कम क्रम-शक्ति की सबसे बड़ी वजह बन गई। जब कोई अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से केम मूल्य वाले कार्यों, जैसे असेंबली, पैकेजिंग या आउटसोर्सिंग पर निर्भर रहती है, तो वहां मजदूरी स्वाभाविक रूप से सीमित रहती है और आय में तेज वृद्धि संभव नहीं हो पाती।

कम आय का सोधा अर्थात् ग्लोबल खराब पर पड़ता है, जिससे बाजार की मांग कमजोर रहती है और आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्यम वर्ग पर पड़ता है, जो एक ओर बढ़ती महंगाई से संकुचित है और दूसरी ओर सीमित वित्त वृद्धि के कारण अपनी जीवन-शैली और आकांक्षाओं को लगातार संभरने से मजबूर होता है। अर्थशास्त्र में इस स्थिति को 'मिडिल क्लास ट्रैप' कहा जाता है, जहां कोई देश गरीबी से तो बहार निकल आता है, लेकिन नवाचार और उच्च मूल्य सृजन के अभाव में विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दृष्टिगत पर ही अटक कर जाता है।



प्रतिकल्पन।

समृद्ध वैश्विक अनुभव यह सिद्ध करता है कि किसी देश की आर्थिक शक्ति का आधार कम मजदूरी नहीं, बल्कि नवाचार, उत्पादकता और तकनीकी बढ़त होती है। अमेरिका, जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में औसत मजदूरी विश्व के सर्वोच्च स्तरों में है, फिर भी ये देश वैश्विक बाजारों में अग्रणी बने हुए हैं। इसका कारण यह है कि उनकी अर्थव्यवस्थाएं केवल निर्माण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अनुसंधान एवं विकास, डिजाइन, ब्रांडिंग, पेटेंट और उच्च मूल्य संपर्क पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए, जर्मनी की 'मिडलस्टैट' कंपनियों अत्यधिक विशिष्ट तकनीकों उत्पाद बनाती हैं, जिनका कोई सस्ता विकल्प विश्व में उपलब्ध नहीं होता। जापान और अमेरिका नवाचार के माध्यम से ऐसे उत्पाद और तकनीक विकसित करते हैं, जिनकी मांग मूल्य से अधिक गुणवत्ता और विश्वसनियता पर आधारित होती है।

वास्तविक संपर्कः प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थामस स्टुअर्ट ने अपनी पुस्तक 'द वैल्यू ऑफ नारेलेंज' में स्पष्ट रूप से कहा है कि 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में असली पूंजी श्रम या प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, अर्थात् ज्ञान, नवाचार और कोशल। आज विश्व में वही देश आर्थिक रूप से समृद्ध और विश्व में रोजगार सृजन करने में सक्षम है जो अनुसंधान एवं विकास को रणनीतिक प्राथमिकता मानते हैं और डिजाइन, पेटेंट, सॉफ्टवेयर तथा ब्रांड जैसे

उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में नेतृत्व स्थापित करते हैं। इसी कारण जर्मनी अपनी उन्नत इंजीनियरिंग, दक्षिण कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीक, जापान उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्माण और अमेरिका वैश्विक नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बने हुए हैं। इन देशों की सफलता इस तथ्य को रेखांकित करती है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में वास्तविक संपर्क हाथों की मेहनत से नहीं, बल्कि दिमाग की क्षमता से पैदा होती है।

डिजिटल इंडिया से डिजाइन इंडिया की ओर

डिजिटल इंडिया की उपलब्धियों के बाद अब देश के सामने अधिक निर्णायक लक्ष्य 'डिजाइन इंडिया' को और बढ़ना है। भारत के पास आज एक ऐतिहासिक अवसर उपलब्ध है, एक विशाल युवा शक्ति, तेजी से मजबूत होता डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक टेक कंपनियों की सख्ती उपस्थिति। लेकिन केवल कोड लिखना या सेवाएं देना ही किसी राष्ट्र को तकनीकी महाशक्ति नहीं बनाता। इसके लिए डिजाइन, डेवलपमेंट, डिस्कवरी और डिफिकल्पन- इन चारों क्षेत्रों में निरंतर आसक्ति है। जब तक भारत अपने सेमीकंडक्टर और चिप स्वयं विकसित नहीं करता, अपनी तकनीकों पर पेटेंट नहीं लगाता, अपने उच्च शिक्षण संस्थानों को वास्तविक रिसर्च हब में परिवर्तित नहीं करता और उद्योग तथा शिक्षा के बीच गहरी साझेदारी स्थापित नहीं करता, तब तक देश की अर्थव्यवस्था उच्च मूल्य सृजन की ओर नहीं बढ़

पाएगी और आम नागरिक की क्रम-शक्ति सीमित ही बनी रहेगी। नीति-निर्माताओं के लिए संदेश विष्कूल स्पष्ट है कि यदि वास्तव में विकसित भारत के सपने को साकार करना है, तो सोच और प्राथमिकताओं में बुनियादी बदलाव करना होगा। शिक्षा को अब केवल सरकारी खर्च के रूप में नहीं, बल्कि दीर्घकालिक राष्ट्रीय निवेश के रूप में देखा होगा। नवाचार को केवल स्टार्टअप संस्कृति तक सीमित रखने के बजाय उसे उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सभी क्षेत्रों तक विस्तार देना होगा। इसके साथ ही अनुसंधान एवं विकास को सरकारी और निजी, दोनों स्तरों पर संगठित और निरंतर समर्थन देना अनिवार्य है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि युवाओं को केवल नौकरियों खोजने के लिए तैयार करने के बजाय उन्हें नौकरी खोजने के लिए तैयार करने वाला, नवाचार करने वाला और मूल्य पैदा करने वाला बनाया जाए, क्योंकि

किसी भी राष्ट्र का भविष्य युवा पीढ़ी की रचनात्मक क्षमता पर ही टिका होता है। आज जब विश्व चौथी औद्योगिक क्रांति में प्रवेश कर रहा है तो वह समझना चाहिए कि राष्ट्रों का निर्माण केवल हाथों की मेहनत से नहीं, बल्कि दिमागों की शक्ति से होता है। ऐसे में आज आवश्यकता है लोगों की तुलना में दिमागों में अधिक निवेश करने की, निर्माण से आगे बढ़कर सृजन को प्राथमिकता देने की और सस्ते उत्पादन की मानसिकता से बाहर निकलकर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की दिशा में कदम बढ़ाने की। यदि भारत को अपनी बनाता की क्रम-शक्ति में वास्तविक वृद्धि करनी है और देश को वास्तविक अर्थ में विकसित बनाना है, तो शिक्षा और नवाचार को केवल नीति का हिस्सा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाना ही होगा, क्योंकि एक भविष्य को जोड़कर नहीं, बल्कि भविष्य को गहूकर विकसित करते हैं। (शिवराज प्रसाद)

आधारित विकास को और ले जाना होगा। वर्तमान में भारत उच्च शिक्षा और शोध पर अपनी संकलन परेल्स उत्पाद का मात्र 0.37 से 0.4 प्रतिशत ही खर्च करता है, जो वैश्विक मानकों की तुलना में अत्यंत कम है। इसके विपरीत चीन इस क्षेत्र में लगभग 1.2 प्रतिशत और अमेरिका 1.7 प्रतिशत से अधिक निवेश करता है, जबकि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (आईईसीडी) देशों में यह अनुपात और भी कंचा है। शिक्षा और अनुसंधान

में निवेश का यही अंतर तब करता है कि किसी देश भविष्य की तकनीक, उत्पाद और विचारों का निर्माता बनेगा और कम केवल दूसरों द्वारा विकसित नवाचारों का उपयोगकर्ता बनकर रह जाएगा। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संस्थानों ने भी इस विषय पर बार-बार चेतावनी दी है। विश्व बैंक की रिपोर्ट 'द इन्वेंशन पारोडोक्स' स्पष्ट रूप से कहती है कि विकासशील देश नवाचार और उच्च शिक्षा में अपेक्षाकृत

कम निवेश करते हैं, जबकि इन्हीं क्षेत्रों से मिलने वाला प्रतिफल सबसे अधिक होता है। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास समन्वयन और आईसीडी लगातार यह रेखांकित करते रहे हैं कि कोशल विकास, अनुसंधान, तकनीकी शिक्षा और एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम के बिना कोई भी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल उपभोक्ता की भूमिका से बाहर निकलकर मूल्य सृजन करने वाला राष्ट्र नहीं बन सकता।